Dr Babita Pathak, Hod department of commerce

Durga College Raipur

Introduction of Goods and service Tax

उत्पत्ति

भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रचलित जटिल और खंडित कर संरचना को एक एकीकृत प्रणाली से बदलना था जो अनुपालन को सरल बनाएगी, कर के बोझ को कम करेगी और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। एकीकरण। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने 2009 में पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोडमैप तैयार किया। संविधान संशोधन विधेयक 2011 में पेश किया गया था लेकिन राज्यों को मुआवजे और अन्य मुद्दों के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वर्षों के विचार-विमर्श और बातचीत के बाद, संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 संसद में पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संविधान में संशोधन करना था। संविधान संशोधन विधेयक मई, 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक अंततः राज्यसभा में पारित किया गया और उसके बाद अगस्त, 2016 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके अलावा, विधेयक को आवश्यक संख्या में अनुमोदित किया गया है। राज्यों और 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया। जीएसटी परिषद को 15 सितंबर से अधिसूचित किया गया था। सितंबर, 2016. जीएसटी परिषद की सहायता के लिए जीएसटी परिषद सचिवालय का कार्यालय भी स्थापित किया गया।

जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे, की स्थापना कर दरों, छूट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए की गई थी। इसने भारत में जीएसटी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 जुलाई, 2017 को, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल को प्रतिस्थापित करते हुए जीएसटी कानून लागू किया गया था । भारतीय जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को 5%, 12%, 18% और 28% सहित विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। कुछ आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है, सोने और हीरे के लिए जॉब वर्क पर कर की दर कम है। अवगुण वस्तुओं और सेराटिन लक्जरी वस्तुओं पर मुआवजा उपकर लगाया जा रहा है।

जीएसटी के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए, आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और कर अधिकारियों और व्यवसायों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन), एक गैर-लाभकारी कंपनी, करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए आईटी रीढ़ प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।

इसके कार्यान्वयन के बाद से, भारतीय जीएसटी में व्यवसायों की प्रतिक्रिया और उभरते आर्थिक परिदृश्य के आधार पर विभिन्न संशोधन और परिशोधन हुए हैं। जबकि जीएसटी कार्यान्वयन ने शुरुआत में व्यवसायों के लिए नई अनुपालन आवश्यकताओं को समझने और परिवर्तनों को अपनाने के मामले में चुनौतियां पेश कीं, लेकिन यह धीरे-धीरे भारतीय कर परिदृश्य में बस गया है।

यह कहा जा सकता है कि भारत में जीएसटी का इतिहास देश की कर संरचना में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य व्यवसायों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए अधिक एकीकृत, कुशल और पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बनाना है।

जीएसटी और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

जीएसटी के कार्यान्वयन से भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में मौलिक बदलाव आया है। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार साझा करती हैं। इससे राज्यों में कर संरचना में अधिक सामंजस्य और एकरूपता आई है, जिससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है।

जीएसटी प्रणाली दोहरी संरचना का अनुसरण करती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल हैं, जो क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार एकत्र करती है लेकिन गंतव्य राज्य में विभाजित करती है।

राजस्व वितरण के मामले में, जीएसटी परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक संयुक्त मंच है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेती है। एक निर्णय को छोड़कर परिषद् के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये।

जीएसटी व्यवस्था में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने और राज्यों को होने वाले किसी भी राजस्व घाटे को संबोधित करने के लिए, एक मुआवजा तंत्र स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार जीएसटी कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसी भी राजस्व कमी के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी। यह मुआवजा अपेक्षित राजस्व वृद्धि और राज्यों द्वारा एकत्र किए गए वास्तविक राजस्व के बीच अंतर को पाटने के लिए था।

इसने अधिक समन्वय को बढ़ावा दिया है, कर बाधाओं को कम किया है और कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। जीएसटी का सफल कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक और सर्वसम्मति-आधारित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसने वित्तीय संबंधों को बदल दिया है, जिससे भारतीय कर प्रणाली में अधिक समन्वय और दक्षता सुनिश्चित हुई है।\

जीएसटी की मुख्य विशेषताएं

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यहां जीएसटी की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं:

a. **एक राष्ट्र, एक कर:** जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों, जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर (वैट) और अन्य का स्थान ले लिया। इसने पूरे भारत में कर संरचना में एकरूपता ला दी, जिससे करों का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया।

b. **दोहरी संरचना:** जीएसटी दोहरी संरचना के तहत संचालित होता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल है। अंतर-राज्यीय लेनदेन के मामले में, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार एकत्र करती है और संबंधित राज्य को वितरित करती है। वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और लागू सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी के अधीन होगा।

c. **गंतव्य-आधारित कर:** जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है, जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति मिलती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है।

d. **इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी):** जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देता है, जिसमें व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या प्रावधान में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। इससे दोहरे कराधान से बचने में मदद मिलती है और कुल कर देनदारी कम हो जाती है।

e. मानव उपभोग के लिए शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा। पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस) पर जीएसटी जीएसटीसी द्वारा अनुशंसित तिथि से लागू होगा। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होंगे। इसके अलावा, केंद्र के पास इन उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति होगी। निर्यात शून्य-रेटेड आपूर्ति हैं। इस प्रकार, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर इनपुट कर या तैयार उत्पादों पर कर नहीं लगेगा।

f. **सीमा छूट:** एक निर्दिष्ट सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यवसाय (वर्तमान में, भारत में सेवाओं/वस्तुओं और सेवाओं दोनों के आपूर्तिकर्ता के लिए सीमा ₹ 20 लाख और माल के आपूर्तिकर्ता (इंट्रा-स्टेट) के लिए ₹ 40 लाख है) को जीएसटी से छूट दी गई है। . कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम को छोड़कर वस्तुओं और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए सीमा ₹ 10-20 लाख के बीच भिन्न होती है, जहां सेवाओं/वस्तुओं और सेवाओं दोनों के आपूर्तिकर्ता के लिए सीमा ₹ 20 लाख है। माल के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 40 लाख (इंट्रा-सेट)। यह सीमा छोटे पैमाने के व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने में मदद करती है।

g. **कंपोजीशन स्कीम:** कंपोजीशन स्कीम एक निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है (वर्तमान में ₹ 1.5 करोड़ और विशेष श्रेणी वाले राज्य के लिए ₹ 75 लाख)। इस योजना के तहत, व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में भुगतान करना आवश्यक है और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना है।

h. **ऑनलाइन अनुपालन:** जीएसटी ने पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, करों का भुगतान और अन्य अनुपालन-संबंधित गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) पेश किया। इसने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और करदाताओं के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना आसान बना दिया।

i. **मुनाफाखोरी विरोधी उपाय:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) की स्थापना की। एनएए ने निगरानी की और सुनिश्चित किया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण व्यवसाय अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में संलग्न न हों। सभी जीएसटी-मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें अब 1 दिसंबर 2022 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निपटाई जाएंगी।

j. **अनुपालन और पारदर्शिता में वृद्धि:** जीएसटी का उद्देश्य अधिक व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर कर अनुपालन को बढ़ाना है। कर प्रणाली की पारदर्शी प्रकृति, प्रक्रियाओं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के साथ, कर चोरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है।

k. **क्षेत्र-विशिष्ट छूट:** स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खाद्यान्न जैसी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कुछ क्षेत्रों को या तो जीएसटी से छूट दी गई है या सामर्थ्य और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कर दरों में कमी की गई है।

l. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले एसजीएसटी का क्रेडिट निर्यातक राज्य द्वारा केंद्र को हस्तांतरित किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच समय-समय पर खातों का निपटान किया जाएगा। इसी प्रकार, एसजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला आईजीएसटी केंद्र द्वारा आयातक राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, बी2सी आपूर्ति पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी हिस्सा भी केंद्र द्वारा गंतव्य राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न में निहित जानकारी के आधार पर धन का हस्तांतरण किया जाएगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी ढांचा परिवर्तन के अधीन है और अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों और सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर संशोधन पारित किए जाते हैं।